

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

लोक उद्यम भवन
ब्लॉक सं. 14, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 24 जनवरी, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: - केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) में गैर-संघीय पर्यवेक्षकों सहित बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के पदों पर दिनांक 01.01.1997 से वेतनमानों का संशोधन - संशोधित दरों पर आईडीए का भुगतान से संबंधित।

अधोहस्ताक्षरी को डीपीई के दिनांक 25.06.1999 के कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध-III में नई डीए योजना का अवलोकन करने का निदेश हुआ है, जिसमें बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और सीपीएसईज़ के गैर-संघीय पर्यवेक्षकों को देय डीए की दरों को इंगित किया गया है। सीपीएसईज़ के अधिकारियों और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों को देय डीए की दर दिनांक 01.01.2022 से 379.6% है।

- डीए की उपरोक्त दर अर्थात् 379.6% आईडीए कर्मचारियों के मामले में लागू होगी, जिन्हें डीपीई के दिनांक 25.06.1999 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार संशोधित वेतनमान (1997) की अनुमति दी गई है।
- भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त को आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के ध्यान में लाएं।
- इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(समसुल हक)
अवर सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

- केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
- प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में वित्तीय सलाहकार।
- व्यय विभाग, ई-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
- भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ की इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

(समसुल हक)
अवर सचिव